



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 322]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 16, 1976/आसाधा 25, 1898

No. 322]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 16, 1976/ASADHA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th July, 1976

S. O. 478(E)/18A/IDRA/76.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S. O. 4460/18A/IDRA/67, dated the 14th December, 1967, namely:—

In the said Order,—

(a) in paragraph 1, for the words and brackets “the body of persons (in this Order referred to as the Board of Management)”, the words “the Bihar State Sugar Corporation Private Limited” shall be substituted;

(b) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“2. The Central Government may issue from time to time such directions, as it may consider necessary, in respect of appointment of supervisory and executive staff and their salary and allowances, and pension contributions of the Government servants employed in connection with the management of the Industrial Undertaking”;

(c) paragraphs 3 and 4 shall be omitted and paragraph 5 shall be renumbered as paragraph 3.

[No. F-4/13/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1976

का०छा० 478(अ)/18क/आई डी आर ए/76.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 4460/18क/आई० डी० आर ए/67, तारीख 14 दिसम्बर, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में,—

(क) पैरा 1 में, “व्यक्तियों के निकाय” (जिसे इस आदेश में प्रबन्ध बोर्ड कहा गया है) शब्दों के स्थान पर “बिहार स्टेट शूगर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड” शब्द रखे जायेंगे ।

(ख) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2. केन्द्रीय सरकार पर्यवेक्षी और कार्यपालक कर्मचारी वृन्द को नियुक्ति और इनके वेतन तथा भत्तों, और औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध के सम्बंध में नियोजित सरकारी कर्मचारी के पेंशन अभिदायों की बाबत समग्र समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।” ।

(ग) पैरा 3 और 4 का लोप किया जाएगा और पैरा 5 को पैरा 3 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

[सं० फा-4/13/72—सीयूसी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976